(c) and (d) The farmers of important cotton growing Districts of Andhra Pradesh have been hesitant to sell their produce in expectation of higher prices. However, with increased volume of purchases by the Cotton Corporation of India (CCI), their has been an increase in prices by 7 to 20 per cent over and above the Minimum Support Prices in Andhra Pradesh. The Government have also released additional export quota of two lakh bales of long staple cotton for providing the growers the benefit of higher prices.

देश में तिलहनों का उत्पादन

495. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले खरीफ मौसम के दौरान देश में तिलहन के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मौसम के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि तिलहनों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद खाद्य तेलों के आयात का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) और (ख) दिनांक 28/29 सितम्बर, 1989 को हुए रबी अभियान के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों के आधार पर, 1989-90 के खरीफ मौसम में तिलहनों का कुल उत्पादन 97.65 लाख मीटरी टन होने की आशा है, जबकि खरीफ 1988-89 के दौरान 103.03 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था।

(ग) और (घ) देश में बढ़ती हुई मांग तथा देशी उत्पादन में से सप्लाई की क्षमता के अन्तर को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का आयात किया जाता है। तेल वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्य तिलहनों के उत्पादन के इस समय के अनुमान के आधार पर देश में खाद्य तेल का मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर हो सकता है।

देश में वृद्धावस्था पेंशन का दिया जाना

496. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हाल ही में इन राज्य सरकारों द्वारा ऐसी पेंशनों की राशि में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार एक समान योजना बनाने और उसे समस्त देश में कार्यान्वित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संसाधन स्थिति के आधार पर समय-समय पर पेंशन दरों में संशोधन करते रहते है। 1985 और 1988 के बीच विभिन्न राज्यों में पेंशन दरों में वृद्धि दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं (नीचे देखिये)।

(ग) और (घ) वृद्धावस्था पेंशन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा राज्यों द्वारा अपने संसाधनों में से इनका भुगतान किया जाता है। इस समय वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1985 में पेंशन दर	1988 के दौरान पेंशन दर	शुद्ध वृद्धि
1. आंध्र प्रदेश	30.00	30.00	—
2. अरुणाचल प्रदेश	60.00	60.00	—
3. असम	60.00	60.00	—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1985 में पेंशन दर	1988 के दौरान पेंशन दर	शुद्ध वृद्धि
4. बिहार	30.00	30.00	—
5. गोवा	60.00	60.00	—
6. गुजरात	30.00	60.00	30.00
7. हरियाणा	60.00	100.00	40.00
8. हिमाचल प्रदेश	50.00	60.00	10.00
9. जम्मू एवं काश्मीर	50.00	60.00	10.00
10. कर्नाटक	50.00	50.00	—
11. केरल	55.00	55.00	—
12. मध्य प्रदेश	60.00	60.00	—
13. महाराष्ट्र	60.00	100.00	40.00
14. मणिपुर	60.00	60.00	—
15. मेघालय	60.00	60.00	—
16. मिजोरम	60.00	60.00	—
17. नागालैण्ड	60.00	60.00	—
18. उड़ीसा	40.00	40.00	—
19. पंजाब	50.00	50.00	—
20. राजस्थान	40.00	50.00	10.00
दंपति—	50.00		
21. सिक्किम	60.00	60.00	—
22. तमिलनाडु	35.00	35.00	—
23. त्रिपुरा	45.00	75.00	30.00
24. उत्तर प्रदेश	40.00	60.00	20.00
25. पश्चिम बंगाल	30.00	60.00	30.00
संघ राज्य क्षेत्र:			
26. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	60.00	60.00	—
27. चण्डीगढ़	60.00	60.00	—
28. दादर एवं नागर हवेली	60.00	60.00	—
29. दमन एवं दीव	60.00	60.00	—
30. दिल्ली	60.00	100.00	40.00
31. लक्षद्वीप	60.00	100.00	40.00
32. पाण्डिचेरी	50.00	60.00	10.00

सूचना स्रोतः (1) कल्याण मंत्रालय भारत भारत सरकार के योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रभाग द्वारा प्रकाशित समाज कल्याण सांख्यिकी हैंडबुक।

(2) कल्याण मंत्रालय के योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग प्रभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से एकत्रित सूचना।